**पद्मसुंदर राव (मृत) और अन्य**

**बनाम**

**तमिलनाडु राज्य और अन्य**

13 मार्च, 2002

[एस.पी. भरूचा, मुख्य न्यायधीश, आर.सी. लाहोटी, एन. संतोष हेगड़े,

रूमा पाल और अरिजीत पसायत, न्यायमूर्तिगण]

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894–धारा 6, धारा 6(1) का प्रावधान–घोषणा–पूर्ववर्ती घोषणा न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई–बाद की घोषणा–सीमा–क्या अधिसूचना की तारीख से शुरू होती है 4(1) या रद्द करने या आदेश की तारीख से–निर्णय, सीमा अधिसूचना की तारीख से शुरू होगी, न कि आदेश की तारीख से–भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1967–भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984।*

*कानूनों की व्याख्या–न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो स्पष्ट और अस्पष्ट है–विधायी कैसस ओमिसस को न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा आपूर्ति नहीं की जा सकती–भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894–धारा 6(1)।*

*सिद्धांत:*

*स्टेरे डेसिसिस–जब किसी न्यायिक निर्णय को निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो लागू होने योग्यता–बाद का कानून।*

*रेशियो डेसिडेंडी–लागू होने योग्यता–न्यायालय इस पर भरोसा न करें–तथ्य की स्थिति की लागू होने योग्यता पर विचार किए बिना।*

**भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) की धारा 4 के तहत अधिसूचना भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के लागू होने से पहले लेकिन भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1967 के बाद जारी की गई थी। धारा 6(1) के तहत घोषणा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी और तीन साल की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जैसा कि इसके प्रावधान जी में निर्धारित है। इसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसके बाद धारा 6 के तहत बाद की अधिसूचना जारी की गई। अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर इसे चुनौती दी कि यह सीमा से बाधित है क्योंकि ऐसी अधिसूचना के लिए सीमा की गणना धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की तारीख से की जानी थी। उच्च न्यायालय ने नरसिम्हिया के मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि यह वैध रूप से जारी किया गया था क्योंकि सीमा की गणना धारा 6 के तहत पहले की अधिसूचना को रद्द करने के आदेश की तारीख से की जानी थी। इसलिए ये अपीलें।**

**धारा 6 के तहत सीमा के सवाल पर इस न्यायालय की विभिन्न बेंचों के बीच मतभेद के मद्देनजर, मामला वर्तमान संविधान पीठ को संदर्भित किया गया था।**

*ए.एस. नायडू* के मामले और *ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल* के मामले में, राय यह थी कि ऐसे मामलों में सीमा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की तारीख से शुरू होगी, जबकि *एन. नरसिम्हाया* के मामले और *डी.सी. नंजुदय्या* के मामले में, अदालत ने कहा था कि सीमा घोषणा को रद्द करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी, न कि धारा 4(1) के तहत मूल अधिसूचना की तारीख से।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 6 का स्पष्ट पठन दर्शाता है कि घोषणा निर्दिष्ट समय के भीतर जारी की जानी है, इसलिए, यदि *नरसिम्हाया* के मामले में राय स्वीकार की जाती है, तो यह अदालत द्वारा कानून बनाना होगा जो अनुमत नहीं है।

प्रतियार्थीयों ने तर्क दिया कि *नरसिम्हाया* के मामले में राय वैधानिक इरादे के अनुरूप थी, इसलिए समय सीमा का विस्तार अनुमेय था; चूंकि *के. चिन्नाथंबी गौंडर* के मामले ने लंबे समय से क्षेत्र को धारण किया था, इसलिए स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत लागू था; और चूंकि कई अधिग्रहण अंतिम हो गए थे और यदि मामलों को फिर से खोला गया और अलग–अलग विचार किए गए, तो यह कठिनाई पैदा करेगा।

न्यायालय ने अपीलों को निस्तारित करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:

1.1. एक बार जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर दिया जाता है, तो धारा 6 के तहत कोई नई घोषणा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की निर्धारित अवधि के बाद जारी नहीं की जा सकती है।

*ए.एस. नायडू और अन्य। आदि बनाम. तमिलनाडु राज्य और अन्य*। आदि, (एसएलपी (सी) क्रमांक 11353–11355/1988 और *ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल बनाम। सरकार तमिलनाडु और अन्य*, (1995] 5 एससीसी 206, पुष्टि की गई।

1.2. यह नहीं कहा जा सकता है कि घोषणा के प्रकाशन के लिए 3 साल की सीमा उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी और अधिनियम की धारा 4(1) के तहत मूल प्रकाशन की तारीख से नहीं।

एन. नरसिम्हाया और अन्य बनाम कनाटक राज्य और अन्य, (1996) 3 एससीसी 88 और कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डी.सी. नंजुडय्या और अन्य, (1996) 10 एससीसी 619 को पलट दिया गया है।

*निदेशक, आयकर निरीक्षण (अनुसंधान), नई दिल्ली और अन्य बनाम पूरन मल और संस और अन्य*, (1975) 2 एससीआर 104; *आयकर आयुक्त, केंद्रीय कलकत्ता बनाम नेशनल ताज ट्रेडर्स*, (1980) 1 एससीसी 370 और *ग्राइंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, कलकत्ता और अन्य*, (1980) 2 एससीसी 191 का उल्लेख किया गया है।

2.1. धारा 6(1) की भाषा स्पष्ट और अस्पष्ट है। इसमें कुछ भी पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि नरसिम्हाया के मामले और नंजुडय्या के मामले में राय को स्वीकार किया जाता है, तो इसका

मतलब यह होगा कि एक मामला धारा 6(1) के प्रावधान के खंड (i) और/या (ii) द्वारा ही नहीं, बल्कि एक गैर–निर्धारित अवधि द्वारा भी कवर किया जा सकता है। यह कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है। किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अधीन किया जाता है, तो यह विधायिका के लिए है कि यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित, संशोधित या निरस्त किया जाए।विधायी कैसस ओमिसस की आपूर्ति न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा नहीं की जा सकती है।अतः, न्यायालय ने यह अभिनिधार्रित किया कि धारा 6(1) के तहत घोषणा जारी करने की सीमा अधिसूचना की तारीख से शुरू होगी और न कि आदेश की तारीख से।

*लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम। येनसवेज़.*, 218 एफआर 547 और *भारत संघ और अन्य. वी. वेदेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा*, एआईआर (1990) एससी 981, संदर्भित।

*एन नरसिम्हैया और अन्य। बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य। आदि,* (1996] 3 एससीसी 88 और *कर्नाटक राज्य और अन्य। बनाम। डी.सी. नंजुदैया और अन्य,* (1996), 10 धारा 619, खारिज कर दिया गया।

2.2. न्यायालय किसी ऐसे वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता जो स्पष्ट और अस्पष्ट हो। एक कानून विधायिका का एक आदेश है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा स्वयं विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। "कानूनों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए", "लेकिन शब्दों को उन उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए जो उनके पीछे हैं"।

2.3. न्यायालय द्वारा कैसस ओमिसस की आपूर्ति केवल स्पष्ट आवश्यकता के मामले में की जा सकती है और जब इसका कारण स्वयं क़ानून के चारों कोनों में पाया जाता है, लेकिन साथ ही एक कैसस ओमिसस को आसानी से नहीं माना जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए क़ानून या अनुभाग के सभी भागों को एक साथ समझा जाना चाहिए और प्रत्येक खंड की व्याख्या संदर्भ और उसके अन्य खंडों के साथ की जानी चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर लगाई जाने वाली व्याख्या पूरे क़ानून का एक सुसंगत अधिनियम बना दे। यह और अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणाम होते हैं जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकते थे। "एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा," "एक क़ानून में नहीं लगाया जाना चाहिए यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है।

*आर्टेमिउ बनाम. प्रोकोपिउ,* (1996) एल क्यूबी 878 और *ल्यूक बनाम आईआरसी। (*1966) ए.सी 557, संदर्भित.

3. यदि अधिसूचना धारा 4(1) के तहत भूमि अधिग्रहण (संशोधन और मान्यकरण) अध्यादेश, 1967 के प्रारंभ होने के बाद और भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने से पहले प्रकाशित की गई थी, तो धारा 6 के तहत घोषणा के लिए सीमा अवधि तीन वर्ष

है। निस्संदेह, अधिसूचना धारा 6(1) के तहत तीन साल की निर्धारित अवधि के भीतर बनाई गई और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, और निर्विवाद रूप से, इसे उच्च न्यायालय द्वारा पहले की कार्यवाही में रद्द कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 6(1) में परिशिष्ट की गई स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि तीन साल की अवधि की गणना में, वह अवधि जिसके दौरान धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के अनुसरण में कोई कार्रवाई या कार्यवाही की जानी है, न्यायालय के आदेश द्वारा रुकी हुई हो, उसे बाहर रखा जाएगा।

*आयकर निरीक्षण निदेशक (जांच) नई दिल्ली एवं अन्य। बनाम। पूरन मल एंड संस एंड अन्य*, (1975] 2 एससीआर 104, भिन्न।

4. स्टेयर डेसिसिस सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित दलील स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है: के. चिन्नाथंबी गौंडर के मामले में निर्णय 1984 अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले दिया गया था। यदि विधायिका का इरादा उन मामलों में नया जीवन देने का था जहां धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर दिया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा नहीं कर सकता था। तथ्य यह है कि विधायिका ने विशेष रूप से स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए प्रावधान किया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किसी अन्य अवधि को बाहर रखने का इरादा नहीं था और सीमा की कोई अन्य अवधि प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

5. न्यायालयों को यह चर्चा किए बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति कैसे फिट होती है जिसमें उस निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति है जिस पर भरोसा किया जा रहा है। किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को इस तरह मानने में हमेशा खतरा होता है कि वे एक वैधानिक अधिनियम में शब्द हैं, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक उद्धार एक विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं। परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है।

*हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड,* (1972) 2 डब्लूएलआर 537, संदर्भित।

6. जिन मामलों में अंतिमता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें नहीं खोला जाना चाहिए। वर्तमान निर्णय इस सीमा तक प्रभावी होगा कि जहां अधिनिर्णय किए गए हैं और मुआवजा भुगतान किया गया है, वहां वर्तमान निर्णय के अनुपात को लागू करके नहीं खोला जाएगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सी की सिविल अपील संख्या 2226 /1997.

चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.3.96 से 1996 के डब्ल्यू.ए. संख्या 106 में।

साथ

सीए। 2002 का 2058.

वी. बालचंद्रन, एस. अरविंद, सेन वें द्वितीय जगदीसन और वी. सी.ए. रामसुब्रमण्यम में अपीलकर्ता के लिए क्रमांक 2226/97 मे।

के. वी. विश्वनाथन, के.वी. वेंकटरमन, अतुल कुमार सिन्हा,'डी सी.ए, कुँवर अजीत मोहन सिंह अपीलकर्ता के लिए बी.रघुनाथ सं. ई 2058/2002 मे।

टी.एल. विश्वनाथ अय्यर और आर. मोहन, वी. बालाजी, पी.एन. रामलिंगम और वी.जी. प्रगासम उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा:** तीन न्यायमूर्तिगण की न्यायमूर्तिगण द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों में विभाजन को देखते हुए, दो न्यायमूर्तिगण ने इस मामले को तीन न्यायमूर्तिगण की न्यायमूर्तिगण के पास भेजा, और 30.10.2001 के आदेश द्वारा इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया, और इस तरह यह मामला सी.ए. क्रमांक 2226/1997 में हमारे समक्ष है। विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 12806/2000 को सिविल अपील के साथ सुना जाने का निर्देश दिया गया था।

एसएलपी क्रमांक 12806/2000 में अनुमति दी गई।

विवाद बहुत ही संकीर्ण दायरे में है, वह यह है कि क्या धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द करने के बाद राज्य सरकार को धारा 6 के तहत एक और अधिसूचना जारी करने के लिए एक वर्ष की नई अवधि उपलब्ध है। वर्तमान मामले में धारा 6 के तहत जारी ऐसी अधिसूचना को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने एन. नरसिम्हाया और अन्य बनाम कनाटक राज्य और अन्य, (1996) 3 एससीसी 88 के निर्णय पर भरोसा किया और माना कि इसे वैध रूप से जारी किया गया था।

अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक अप्रकाशित निर्णय ए.एस. नायडू और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, (एसएलपी (सी) संख्या 11353–11355/1988) पर भरोसा किया, जिसमें तीन न्यायमूर्तिगण की न्यायमूर्तिगण ने माना कि एक बार जब अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर दिया जाता है, तो धारा 6 के तहत कोई नई घोषणा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की निर्धारित अवधि के बाद जारी नहीं की जा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, (1995) 5 एससीसी 206 में दो न्यायमूर्तिगण का एक और निर्णय है, जो ए.एस. नायडू के मामले (उपर्युक्त) में व्यक्त किए गए विचार के समान है। हालांकि, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डी.सी. नंजुडय्या और अन्य, (1996) 10 एससीसी 619 में, नरसिम्हाया के मामले (उपर्युक्त) के दृष्टिकोण का पालन किया गया था और यह माना गया था कि घोषणा के प्रकाशन के लिए 3 साल की सीमा उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी और उस तारीख से नहीं जिस दिन धारा 4(1) के तहत मूल प्रकाशन किया गया था।"

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 6 का एक नंगे पठन, जैसा कि अधिनियम 68/1984 द्वारा संशोधित किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि धारा 6 के तहत घोषणा निर्दिष्ट समय के भीतर जारी की जानी है और केवल इसलिए कि न्यायालय ने संबंधित घोषणा को रद्द कर दिया है, विस्तारित समय अवधि प्रदान नहीं की जानी चाहिए। स्पष्टीकरण । (धारा में जोड़ा गया) विशेष रूप से निर्दिष्ट मामलों में अवधियों के बहिष्करण से संबंधित है। यदि नरसिम्हाया के मामले (उपर्युक्त) में व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि क़ानून में कुछ ऐसा पढ़ना जो वहां नहीं है, और वास्तव में इसका मतलब यह होगा कि न्यायालय द्वारा कानून बनाना, जबकि यह विधायिका के पूर्ण डोमेन के भीतर है। इसके विपरीत, तमिलनाडु राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नरसिम्हाया के मामले (उपर्युक्त) में बताए गए तर्क वैधानिक इरादे के अनुरूप हैं। आयकर निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान), नई दिल्ली और अन्य बनाम पूरन मल और संस और अन्य, (1975) 2 एससीआर 104 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि समय सीमा के विस्तार की अनुमति है। पूरन मल के मामले (उपर्युक्त) के अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम') के तहत कार्यवाही के संबंध में दिए गए दो निर्णयों पर भरोसा किया गया, यह तर्क देने के लिए कि समय सीमा के विस्तार की गुंजाइश है, हालांकि निश्चित वैधानिक समय सीमा थी। जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे हैं आयकर आयुक्त, केंद्रीय कलकत्ता बनाम नेशनल ताज ट्रेडर्स, (1980) 1 एससीसी 370 और ग्राइंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, कलकत्ता और अन्य, (1980) 2 एससीसी 191। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि ग्राइंडलेज के मामले (उपर्युक्त) में, सीमा के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कार्रवाई की गई थी।यह तर्क दिया गया था कि अधिकतम, इसे कैसस ओमिसस का मामला माना जा सकता है, और यदि कोई है, तो क़ानून को समग्र रूप से पढ़कर और सही वैधानिक इरादे का पता लगाकर, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या द्वारा कमी को पूरा किया जा सकता है। के. चिन्नाथंबी गौंडर और अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, एआईआर (1980) मद्रास 251 में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए दृढ़ता से भरोसा किया गया था कि उक्त मामले में व्यक्त किए गए विचार लंबे समय से क्षेत्र में हैं और स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत लागू होते हैं। अंततः, यह प्रस्तुत किया गया था कि कई अधिग्रहण अंतिम हो गए हैं और यदि अलग–अलग दृष्टिकोण लिया जाता है, तो मामलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया जाता है, तो यह कठिनाई का कारण होगा।

> धारा 6(1), उपधारा (2) के तहत किसी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जब उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो जाती है कि किसी विशेष भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए है, तो ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन उस आशय की घोषणा की जाएगी और धारा 4(1) के तहत एक ही अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भूमि के विभिन्न पार्सल के संबंध में अलग–अलग घोषणाएं समय–समय पर की जा सकती हैं, भले ही धारा 5–ए(2) के तहत एक रिपोर्ट या विभिन्न रिपोर्ट बनाई गई हों (जहां भी आवश्यक हो):
>
> परंतु धारा 4(1) के तहत अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भी विशेष भूमि के संबंध में कोई घोषणा अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय के बाद नहीं की जाएगी, जब तक कि न्यायालय द्वारा आदेश न दिया गया हो।

(i) यदि अधिसूचना भूमि अधिग्रहण (संशोधन और मान्यकरण) अध्यादेश, 1967 के प्रारंभ होने के बाद और भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने से पहले प्रकाशित की गई थी, तो घोषणा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद की जाएगी; या

(ii) यदि अधिसूचना भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने के बाद प्रकाशित की गई थी, तो घोषणा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद की जाएगी।

तथ्यात्मक परिदृश्य के रूप में, वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी और घोषणा 24.8.1984 से प्रभावी अधिनियम 68/1984 द्वारा धारा 6(1) के मौजूदा प्रावधान को प्रतिस्थापित करने से पहले की गई थी। दूसरे शब्दों में, धारा 4(1) के तहत अधिसूचना भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने से पहले जारी की गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 1967 (भूमि अधिग्रहण द्वारा प्रतिस्थापित) के प्रारंभ होने के बाद जारी की गई थी। (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 1967 (अधिनियम 13/1967))। लेकिन प्रतिस्थापित प्रावधान विवादित निर्णय की तिथि पर लागू था। प्रावधान के अनुसार, अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भी भूमि के संबंध में धारा 6 के तहत घोषणा तीन वर्ष या एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं की जा सकती है, जैसा भी मामला हो। प्रावधान दो प्रकार की स्थितियों से संबंधित है। यह इस पर निर्भर करते हुए विभिन्न सीमा अवधियों के लिए प्रावधान करता है कि क्या (i) धारा 4(1) के तहत अधिसूचना भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 1967 के प्रारंभ होने के बाद प्रकाशित की गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने से पहले, या (ii) इस तरह की अधिसूचना भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के बाद जारी की गई थी। पहले मामले में, अवधि तीन वर्ष है जबकि दूसरे मामले में यह एक वर्ष है। निस्संदेह, धारा 6(1) के तहत अधिसूचना इसके प्रावधान के तहत निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में बनाई और प्रकाशित की गई थी, और निर्विवाद रूप से, इसे उच्च न्यायालय द्वारा पहले की कार्यवाही में रद्द कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 6(1) में संलग्न स्पष्टीकरण । यह प्रावधान करता है कि तीन वर्ष की अवधि की गणना में, वह अवधि जिसके दौरान धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित की जाती है, को बाहर रखा जाएगा। तमिलनाडु अधिनियम 41/1980 के तहत, दिनांक 20.1.1980 से प्रभावी, प्रयोग किया जाने वाला भाव "कार्रवाई या कार्यवाही ... स्थगन या निषेधाज्ञा के कारण रोक दी गई है", जो प्रासंगिक रूप से समान है।

प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता ने ए. पूरनमाल के मामले (उपर्युक्त) में कुछ अवलोकनों का उल्लेख किया, जो उनके द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों की नींव बनाते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूरनमाल का मामला (उपर्युक्त) पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि पर तय किया गया था। न्यायालय ने देखा कि आकलनकर्ता जो चाहता था कि न्यायालय सीमा के आधार पर राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई को रद्द करे, उसने स्वयं अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने की बात स्वीकार की थी। इसलिए, न्यायालय ने माना कि आकलनकर्ता अपने स्वयं के कार्य का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि समय सीमा की गणना आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के संबंध में निर्धारित अवधि के संदर्भ में की जानी थी। यह देखा गया कि एक बार धारा 132(5) के तहत नब्बे दिनों के भीतर आदेश पारित कर दिया गया है,

तो पीड़ित व्यक्ति को धारा 132(11) के तहत अधिसूचित प्राधिकरण से तीस दिनों के भीतर संपर्क करने का अधिकार है और वह प्राधिकरण आयकर अधिकारी को नया आदेश पारित करने का निर्देश दे सकता है। यह अधिनियम की धारा 6 की तुलना में विशिष्ट विशेषता है। न्यायालय ने त्याग के सिद्धांत को लागू किया और अन्य बातों के साथ–साथ यह माना कि उसमें निर्धारित सीमा अवधि उस व्यक्ति के लाभ के लिए है जिसकी संपत्ति जब्त की गई है और उस व्यक्ति के लिए उस लाभ को त्यागना खुला है। यह आगे देखा गया कि यदि निर्दिष्ट अवधि को अनिवार्य माना जाता है, तो यह नागरिकों को राजस्व से अधिक नुकसान पहुंचाएगा। निर्धारण के लिए सीमा अवधि प्रदान करने वाली विधियों के साथ अंतर किया गया था। यह देखा गया कि धारा 132 आय की कराधान से संबंधित नहीं है। उस पृष्ठभूमि में विचार करने पर, पूरनमाल के मामले में निर्णय का अनुपात (उपर्युक्त) वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

अदालतों को बिना चर्चा किए निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति उस निर्णय के तथ्यात्मक स्थिति के साथ कैसे फिट बैठती है जिस पर भरोसा किया जाता है। यह हमेशा एक विधान में शब्दों के रूप में भाषण या निर्णय के शब्दों का इलाज करने में खतरा है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक उच्चारण किसी विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में किए जाते हैं, जैसा कि हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड में लॉर्ड मॉरिस ने कहा था, (1972) 2 एलएलआर 537। परिस्थितिजन्य लचीलापन, दो मामलों में निष्कर्षों के बीच एक विश्व का अंतर बना सकता है। न्यायालय ने यह देखते हुए कि धारा 132(11) का उपखंड (बी ) केवल आयकर अधिकारी को नया आदेश पारित करने का निर्देश देने के लिए प्राधिकृत करता है, न कि आदेश को रद्द करने के लिए, यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 132(5) के तहत पारित आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।

नारायणमैया के मामले (उपर्युक्त) में तीन–न्यायाधीश की पीठ के साथ जो प्रतीत होता है वह निर्णय की पैरा 12 में सेट किया गया है, जो इस प्रकार है:

> प्रतिवादियों के संबंधित तर्कों पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, अर्थात्, यह धारा 4(1) के तहत प्रकाशन की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होना चाहिए, तो सार्वजनिक उद्देश्य हमेशा विफल हो जाएगा। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है: एक दिए गए मामले में, जहां धारा 4(1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, धारा 5–ए के तहत जांच से छूट दी गई थी और एक महीने के भीतर घोषणा प्रकाशित की गई थी और चूंकि सरकार के विचार में तात्कालिकता इस प्रकार थी कि यह 30 दिनों की देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और तत्काल कब्जा आवश्यक था, लेकिन दिलचस्प व्यक्ति की टालमटोल की रणनीति के कारण कब्जा नहीं लिया गया था और अदालत अंततः दो साल बाद यह पाती है कि तात्कालिकता शक्ति का प्रयोग उचित नहीं था और इसलिए यह न तो वैध था और न ही उचित था और सरकार को दिलचस्प व्यक्ति को अवसर देने का निर्देश दिया था और धारा 5–ए के तहत जांच करने के लिए राज्य, तो अदालत के निर्देश के अनुपालन में शक्ति का प्रयोग निरर्थक होगा क्योंकि जांच करने में समय लगेगा। यदि स्पष्ट कारणों से जांच में देरी होती है, तो धारा 6(1) के तहत घोषणा को धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के मूल प्रकाशन की तारीख से सीमा के भीतर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। धारा 4(1) के तहत एक वैध अधिसूचना अमान्य हो जाती है। दूसरी ओर, अदालत के आदेश के अनुसार जांच करने के बाद, और यदि धारा 6 के तहत घोषणा को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रकाशित किया जाता है, तो

धारा 4(1) के तहत अधिसूचना वैध हो जाती है क्योंकि कार्रवाई अदालत के आदेशों के अनुपालन में की गई थी और अधिनियम की उप–धारा (1) के पहले उप–प्रावधान के खंड (i) और (ii) में निर्धारित सीमा का अनुपालन किया जाएगा।

यह दर्शाता है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्माण, यदि स्वीकार किया जाता है, तो सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर देगा। विधि की पुनर्लेखन और कैसस ओमिसस के संबंध में प्रतिद्वंद्वी याचिकाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय एक सांविधिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं है। एक विधि विधायिका का एक आदेश है। एक विधि में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्णायक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का इरादा विधायिका द्वारा स्वयं प्रयुक्त शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि क्या किया गया है। "विधियों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए"। न्यायाधीश लर्न्ड हैंड ने कहा, "लेकिन शब्दों को उन उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए जो उनके पीछे हैं"। (लेनघ वैली कोल कंपनी बनाम येनसैवेज, 218 एफआर 547 देखें)। यह दृष्टिकोण भारत संघ और अन्य बनाम फिलिप टियागो डी गामा ऑफ वेदेम वुस्को ई डी गामा, एआईआर (1990) एससी 981 में दोहराया गया था।

डॉ. आर. वेंकटचलम और अन्य बनाम उप परिवहन आयुक्त और अन्य, एआईआर (1977) एससी 842 में यह देखा गया कि न्यायालयों को अपनी पूर्व–कल्पित वैचारिक संरचना या योजना के आधार पर एक प्रावधान के अर्थ के पूर्व निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए जिसमें प्रावधान की व्याख्या की जानी है। वे व्याख्या की आड़ में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

एक प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अधीन किया जाता है, तो यह विधायिका के लिए है कि वह इसे संशोधित, संशोधित या निरस्त करे, यदि आवश्यक हो। [देखें ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पीएनबी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, (2000) 5 एससीसी 515]। 'विधायी कैसस ओमिसस को न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा आपूर्ति नहीं की जा सकती है। धारा 6(1) की भाषा स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं है। इसमें कुछ पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नरसिम्हाया के मामले (उपर्युक्त) में किया गया था। नंजुंदैया के मामले (उपर्युक्त) में, अवधि को आगे बढ़ाकर उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से समय अवधि चलाने के लिए कहा गया था। इस तरह के दृष्टिकोण को धारा 6(1) की भाषा के साथ सामंजस्य नहीं किया जा सकता है। यदि दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि एक मामला धारा 6(1) के प्रावधान के खंड (i) और/या (ii) द्वारा ही नहीं, बल्कि एक गैर–निर्धारित अवधि द्वारा भी कवर किया जा सकता है। यह कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है।

दो निर्माण सिद्धांत–एक कैसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा संपूर्ण अधिनियम के रूप में पढ़ने के संबंध में–अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत के तहत, न्यायालय द्वारा कैसस ओमिसस को स्पष्ट आवश्यकता के मामले में और जब इसका कारण स्वयं अधिनियम के चारों कोनों में पाया जाता है, के अलावा किसी अन्य मामले में आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक कैसस ओमिसस को आसानी से नहीं माना जाना चाहिए और इसके लिए पूरे अधिनियम या

अनुभाग के सभी भागों को एक साथ व्याख्यायित किया जाना चाहिए और अनुभाग के प्रत्येक खंड को संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखी जाने वाली व्याख्या पूरे अधिनियम का एक सुसंगत अधिनियमन बनाती है। यह और भी अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुके या विषम परिणामों की ओर ले जाता है जो विधायिका द्वारा नहीं हो सकते थे। "असामान्य परिणाम उत्पन्न करने का इरादा", डेन्कवर्थ्स, एल.जे., ने आर्टेमियो बनाम प्रोकोपिओ, (1966) 1 क्यूं टी 878 में कहा, "यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो इसे अधिनियम में नहीं लगाया जाना चाहिए"। जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करना "विधान के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम उत्पन्न करेगा" हमें "शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी चाहिए" और इस तरह उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करना चाहिए और एक तर्कसंगत निर्माण का उत्पादन करना चाहिए। [लॉर्ड रीड द्वारा ल्यूक बनाम आईआरसी, (1966) एसी 557 में, जहां पृष्ठ 577 पर उन्होंने यह भी कहा: "यह एक नई समस्या नहीं है, हालांकि हमारी ड्राफ्टिंग की मानक ऐसी है कि यह शायद ही कभी उभरती है"।]

स्टेयर डेसिसिस सिद्धांतों की लागू होने के संबंध में याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। के. चिन्नाथंबी गौंडर (उपर्युक्त) मामले में निर्णय 22.6.1979 को दिया गया था, जो कि 1984 अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले का है। यदि विधायिका का उन मामलों में एक नया जीवनदान देने का इरादा था जहां धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर दिया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि वह इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान करके ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। यह तथ्य कि विधायिका ने विशेष रूप से स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधियों के लिए प्रावधान किया है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किसी अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं था और यह कि सीमा की किसी अन्य अवधि को प्रदान करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मदुरै उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उजागर की गई 'एक्टस क्यूरिया नेमिनम ग्रेविबिट' की कहावत का इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति से कोई संबंध नहीं है।

नरसिम्हाया के मामले (उपर्युक्त) और नंजुंदैया के मामले (उपर्युक्त) में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है, जबकि ए.एस. नायडू के मामले (उपर्युक्त) और ऑक्सफोर्ड के मामले (उपर्युक्त) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की जाती है।

हालांकि, इस याचिका में कुछ सार है कि जिन मामलों में अंतिमता प्राप्त हो गई है उन्हें फिर से खोला नहीं जाना चाहिए। वर्तमान निर्णय भविष्य में लागू होगा, इस हद तक कि जिन मामलों में अधिनिर्णय दिए गए हैं और मुआवजे का भुगतान किया गया है, उन्हें वर्तमान निर्णय के अनुपात को लागू करके फिर से खोला नहीं जाएगा। तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है और अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा वाले बाद के अधिसूचना रद्द कर दी जाती है।

के. के. टी अपीलो निस्तारित किया गया।